

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4888 / 2022

बीना देवी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू (राज.)।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, जिला झुंझुनू (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022

आदेश की दिनांक : 13.12.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर बी.सी.एम.ओ., चिडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, खूटों की ढाणी, जिला बाड़मेर किया गया है। उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर किया गया और आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया, उसे अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण किया गया है जबकि अपीलार्थी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित थी। राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार के मामलों को माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रवीन्द्र कुमार टेलर बनाम राज्य एवं अन्य में ऐसे मामलों को अयुक्तियुक्त माना है। आलोच्य आदेश में पंचायती राज विभाग की बिना सहमति के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उक्त नियमों के विरुद्ध है। अपीलार्थी का पुत्र जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उसके अध्ययन के मध्य काल में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया, जिससे अपीलार्थी के पुत्र की पढ़ाई भी बाधित होगी।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर बी.सी.एम.ओ., चिडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप

होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 नियम 8(iii) के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश में सक्षम स्तर पर अनुमोदित अंकित किया गया है, इससे यह प्रकट होता है कि आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 नियमानुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)